गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं। हां एक मंत्रालय में महिला स्वागत अधिकारी का पद है जिस पर एक महिला नियुक्त है।

(ख) विभिन्न कार्यालयों में लड़कियां नियुक्त हैं, किन्तु वे "आरक्षित" पदों पर नियुक्त नहीं हैं। उपरोक्त स्थिति को देखते हुए लड़कियों के लिये आरक्षित पदों के खाली रहने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Amendment of Industrial Disputes Act

3806. Shri Madhu Limaye:
Shri S. M. Banerjee:
Shri George Fernandes:
Shri Ram Manohar Lohia:

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether in view of the rise in the price level, Government intend to amend the Industrial Disputes Act in order to change the definition of workmen so as to include certain supervisory cadres at present excluded and also all those within the income limit of Rs. 1000 per month on the basis of the Memorandum submitted by the State Bank Union;

(b) if so, what supervisory categories are proposed to be included; and

(c) when the amending Bill is likely to be introduced?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi): (a) to (c). The proposal to amend section 2 (s) of the Industrial Disputes Act, 1947 so as to include supervisory and managerial personnel drawing a salary upto Rs. 1600/- p.m. was included in the agenda of the 26th Session of the Standing Labour Committee held at New Delhi on 10th May, 1967 but was not discussed at the meeting for lack of time. It will be placed for discussion at a future meeting of the Standing Labour Committee or the Indian Labour Conference.

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों का हिमाचल प्रदेश में स्थानान्तरण

3807. **श्री ओंकार सिंह :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या गृह-कार्य मंत्री 5 अप्रैल, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 550 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों का हिमाचल प्रदेश में स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में किये गये निर्णय का ब्यौरा क्या है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : जहां तक हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों तथा उससे ऊपर के पदों पर नियुक्तियों का सम्बन्ध है, संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके 75 प्रतिशत प्रतिनियुक्तियों से सम्बन्धित व्यवस्था को समाप्त करने का निश्चय किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से असिस्टेंट इंजीनियरों के पदों में नियुक्ति के लिये वर्तमान 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था को समाप्त करने के बारे में विचार किया जा रहा है।

Delhi Municipal Corporation Amendment Bills

3808. Shri Bal Raj Madhok:
Shri A. B. Vajpayee:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state whether Government intend to introduce afresh the Bills further to amend the Delhi Municipal Corporation Act introduced in the Third Lok Sabha which have lapsed in view of the dissolution of that House?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): The Bills have been referred to the Delhi Administration for being placed before the Delhi Metropolitan Council, as required under section 22 of the